

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 1984 (अग्रहायण 10, 1906)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 1984 (AGRAHAYANA 10, 1906)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और अर्माधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	287
भाग I—खण्ड-2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	—
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और अर्माधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महानिष्ठा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	131
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खंड 2—पेटेंट कार्यालय, कम्पन्स द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	977
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III—खण्ड 3—मुख्य कार्यकर्ता के प्राधिकार के अधीन बचवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड-1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन, और नोटिस शामिल हैं	2981
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रथम समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	181
भाग II—खंड-3-उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	भाग V—संग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकनों को विज्ञापन वाला अनुपूरक	—
भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं		

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—341G1/14

(827)

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	827	PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories) ..	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	1469	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	—	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railways Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	2871
PART I—SECTION 4—Notification regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	1897	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	977
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners ..	—
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations ..	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	2981
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	181
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*	PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1984

सं० ए०-11013/91/84-प्रशा०-I—भारत सरकार ने एक तकनीकी अध्ययन दल नियुक्त करने का फैसला किया है जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की संरचना की विस्तृत जांच करेगा और इस सम्बन्ध में सिफारिश करेगा कि इसे किस आधार पर संशोधित तथा सुनिश्चित बनाया जा सकेगा।

तकनीकी अध्ययन दल में निम्नलिखित शामिल होंगे—

श्री जयानिर्मल दा।

—अध्यक्ष

सदस्य

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।

श्री० चरण प्रकाश

—सदस्य

प्रारंभिक सलाहकार

भारत टैली इलेक्ट्रॉनिक्स

श्री नरेश शर्मा

कार्यकारी निदेशक

भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ

—सदस्य

श्री एन० टी० सीनिवासन

सदस्य (वित्त)

औद्योगिक लागत एवं मूल्य बोर्ड

—सदस्य

सदस्य (बजट)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं

सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली

—सदस्य

जबकि अध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होंगे परन्तु सदस्य, अपने-अपने तन्मान कार्यों के अतिरिक्त दल में कार्य करेंगे।

3. तकनीकी अध्ययन दल के विचारार्थ विषय उभ प्रकार से हैं—

(i) भारत सरकार से इस सम्बन्ध में सिफारिश करना कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ अनुसूची (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और तमक अधिनियम की प्रथम अनुसूची) में जिस आधार पर, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में, संशोधन किए जाने चाहिए।

(क) वर्तमान और पर मसौदाकर्तियों के बीच विवाद का कम करने की दृष्टि से टैरिफ और कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्य-विधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता;

(ख) नीति-निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के भार में सम्बन्धित आधार सामग्री एवम् करने में सुविधा; और

(ग) औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक वाहनों, आयात वाहनों, आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा इससे संबंधित किए जाने वाले

सीमा शुल्क टैरिफ कोड और अन्य मौखिकीय वर्गीकरण के साथ सम्भव सीमा तक मिलान,

(ii) छूट और राहतों विशेष रूप से ऐसे राहतों और छूटों के तरीके की समीक्षा करना जिनका उद्देश्य लघु-उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना हो, और

(iii) दल द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन करने और विशेष रूप से इस बात की जांच करने की दृष्टि से आवश्यक विधायी और प्रशासनिक परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सिफारिश करना कि क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची का हरीर उत्पादन शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में अलग से अधिनियमित किया जाना चाहिए।

4. दल-समय-संगत पर ऐसे समस्याओं को आवश्यकता अनुसार न्यायित कर सकता है तथा उससे ऐसा सुविधा सलाह अथवा दूसरे साधन ले सकता है जो इसके कार्य के लिए अपेक्षित हैं। दल अपनी नियुक्ति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसा प्रस्तावित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधि-कारियों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प का आभाषण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्री० पी० गुप्ता उप सचिव

भारतीय डाक तार विभाग

डाक तार महानिदेशक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1984

प्रस्ताव

सं० 6-29/83-पी० ई-11—भारत सरकार कुछ समय में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्यकरण की जांच करने और अतिरिक्त विभागीय एजेंसियों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के मानदण्ड की पुनरीक्षा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। अब भारत सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक-सदस्य समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

2. श्री आर० आर० सबूर, सेवानिवृत्त सदस्य (वित्त), डाक तार बोर्ड इस समिति का गठन करेंगे।

3. यह समिति समान्यतया डाक-तार विभाग की डाक शाखा की अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के कार्यकरण की जांच करेगी और निम्नव्ययता को ध्यान में रखते हुए, यथावश्यक इस प्रणाली का अधिकार बनाने के लिए इसके

सुधार सम्बन्धी सुझाव देगी। विशेषतः समिति निम्नलिखित कार्यों का अध्ययन करेगी :—

- (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं के लिए उनके पारिश्रमिक के मौजूदा मामूले तथा उनके भत्तों की सावधिक पुनरीक्षा प्रक्रिया की जांच करना।
- (ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को डाकघर कार्य आदि से सम्बन्धित सुविधाएं देने की जांच करना।
- (ग) विभिन्न श्रेणी के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों में जनता की दी गयी सुविधाओं की पुनरीक्षा।
- (घ) विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता तथा अन्य प्रहता शर्तों तथा डाक तार विभाग में उन्हें नियमित ग्रेड में नियुक्त करने के लिए दी गयी सुविधाओं की पुनरीक्षा।
- (ङ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए आचरण और अनुशासनिक नियमावली की पुनरीक्षा।
- (च) इस पर भी विचार करना कि क्या अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को एक उपदान देने की मौजूदा प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्तन करने का आवश्यकता है ?
- (छ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के संगठन की वैधानिक ट्रेड यूनियन के कार्यकलापों सम्बन्धी दी गयी सुविधाओं की पुनरीक्षा।

4. यदि समिति की जांच के दौरान अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्तरिम आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो समिति इस मुद्दे पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा यह भी निश्चित किया जाएगा कि क्या समिति किसी प्रकार की अन्तरिम आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करती है तथा किन तारीख से ऐसी अन्तरिम सहायता दी जाए।

5. समिति अन्य बातों के साथ-साथ डाक तार विभाग की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, साधनों तथा वित्तीय शर्तों, विकासीय योजनाओं की मांगों तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन तथा अन्य सामान्य स्थानीय परिस्थितियों, को ध्यान में रख कर अपनी सिफारिशें देगी। समिति अपने कार्य की प्रगति के बारे में समय-समय पर चतुर्थ वेतन आयोग को सूचित करती रहेगी।

6. समिति अपनी कार्य प्रक्रिया बनाएगी तथा यथावश्यक सूचना एकत्र करेगी और साक्ष्य लेगी।

7. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

8. समिति अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

आदेश दिया जाता है कि जनता के सूचनाईय इस प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति वेतन आयोग, निवेशक, लेखा परीक्षा, डाक-तार, दिल्ली, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) तथा अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित की जाए।

आर० किशोर, सचिव (प्रशासन)
पदेन अतिरिक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 1984

संकल्प

सं० ई०-11015/33/82-हिन्दी—भारत सरकार श्री नरेन्द्र सिंह, सचिव सदस्य का इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई०-11015/1/80-हिन्दी, दिनांक 14 अगस्त, 1984 द्वारा गठित इस मंत्रालय की हिन्दी मन्त्रालय समिति की सदस्यता से स्थापित तत्काल से स्थापित होगी है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों राजपत्र सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, समर्थन कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मन्त्रिमन्त्रालय राष्ट्रीय राजस्व और लेखा महा-नियंत्रक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नरेन्द्र सिंह, जफा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
New Delhi, the 22nd September 1984
RESOLUTION

No. A-11013/91/84-Ad.IV.—The Government of India has decided to appoint a Technical Study Group to conduct a comprehensive enquiry into the structure of the Central Excise Tariff and recommend the lines on which it may be revised and rationalised.

The Technical Study Group will consist of the following :—

Chairman

Shri J. Datta,
Member,
Central Board of Excise and
Customs, New Delhi.

Members

Dr. Charan Wadhawa,
Economic Adviser,
Bharat Heavy Electricals.

Shri Tarun Das,
Executive Director,
Association of Indian
Engineering, Industry.

Shri N. T. Srinivasan,
Member (Finance),
Bureau of Industrial Costs
& Prices.

Member (Budget),
Central Board of Excise &
Customs, New Delhi.

While the Chairman will be full time officers, the Member will be serving the group in addition to their present assignments.

3. The terms of reference of the Technical Study Group are—

- (i) to recommend to the Government of India the lines on which the Central Excise Tariff (First Schedule to the Central Excise & Salt Act, 1974) should be revised with particular reference to—
 - (a) the need for simplification and rationalisation to the Tariff and assessment procedures with a view to reducing the areas of conflict between the tax payers and the tax-collectors;
 - (b) facility in collection of data regarding incidence of excise duty for policy formation; and
 - (c) alignment, to the extent possible, with the Tariff code of Customs and other statistical classification used by the Government in regard to industrial licensing, import licensing etc.
- (ii) to review the pattern of exemptions and reliefs, particularly those aimed at encouraging small scale and cottage industries; and
- (iii) to make recommendations for necessary Legislative and administrative changes with a view

to implementing the recommendations made by the Group and, especially, to examine whether the First Schedule to the Central Excise and Customs Act, 1944 should be separately enacted as Central Excise Tariff Act.

may co-opt such members as may be necessary to time and take such expert or other evidence as it may require for its work. The Group will submit its Report to the Government of India within a year from the date of its appointment; and it may submit such interim reports as it considers necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for General information.

O. P. GULLA, Dy. Secy

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL POSTS AND TELEGRAPHS

New Delhi-110001, the 5th November 1984

RESOLUTION

No. 6-29/83-PE-II.—The question of examining the working of the Extra-Departmental System in the P&T Department and reviewing the basis for remunerating the services of Extra-Departmental Agents has been under the consideration of the Government of India for some time. The Government of India have now decided to set up a One-man Committee for the purpose.

2. Shri R. R. Savoor, retired Member (Finance), P&T Board, will constitute the Committee.

3. The Committee will examine generally the working of the Extra Departmental System in the Postal Wing of the P&T Department and suggest such modifications and improvements as may be necessary to make the system efficient consistent with economy. In particular, the Committee will;

- examine the existing basis for remunerating the services of Extra-Departmental Agents and the procedure for periodical review of their allowances;
- examine the facilities to be provided to Extra Departmental Agents in connection with Post Office work etc.;
- review the facilities provided for the public at different classes of Extra Departmental Post Offices;
- review the qualifications and other eligibility conditions prescribed for employment of different categories of Extra Departmental Agents and the facilities given to them for absorption in the regular grades in the P&T Department;
- review the conduct and disciplinary rules for Extra-Departmental Agents;
- consider whether any change is called for in the present system of grant of gratuity to Extra-Departmental Agents;

(g) review the facilities extended to Association of Extra-Departmental Agents in regard to legitimate Trade Union activities.

4. In case the need for consideration of grant of relief of an interim character to the Extra-Departmental Agents arises during the course of enquiry by the Committee, it may consider the same and send a report thereon. Should the Committee recommend grant of any interim relief, the date from which the relief should be granted will also be indicated by the Committee.

5. The Committee will make its recommendations having regard, among other factors, to the historical background, the resources and financial condition of the P & T Department, the demands of developmental planning and the wages and other conditions of employment prevailing in the localities where such Extra-Departmental Agents are normally employed. The Committee will keep the Fourth Central Pay Commission informed of the progress of its work from time to time.

6. The Committee will devise its own procedure and may call for such information and take such evidence as it may consider necessary.

7. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi.

8. The Committee will make its recommendations within a period of one year from the date of its formation.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Pay Commission, Director of Audit, P & T Delhi, the Ministry of Finance (Department of Expr.) and all others concerned.

R. KISHORE
Member (Administration) &
Ex-Officio-Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 31st October 1984

RESOLUTION

No. F.11015/33/82-Hindi.—Government of India have accepted the resignation of Shri Narendra Singh, Member of Parliament, from the membership of the Hindi Advisory Committee of this Ministry constituted vide this Ministry's Resolution No. F.11015/180-Hindi, dated 14th August, 1984 with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Govts. and Union Territory Administrations, all Ministries/Depts. of the Govt. of India, President's Sectt., Prime Ministers Office, Cabinet Sectt., Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. JAJA, Jt. Secy.

